No. NA-301/5/2021-NA
Government of India
Ministry of Coal
O/o Nominated Authority
****

R. No. 120 'F', Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 01 December 2021

ORDER

Subject :- Amendment in CMDPAs/Allotment Agreements for captive coal mines

.....

Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 has, inter-alia, introduced section 8(5) in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (hereinafter, 'MMDR Act') making an allowance for sale of coal or lignite by any lessee where coal or lignite is used for captive purpose, in the manner prescribed by the Central Government.

2. Thereafter, in exercise of powers conferred by Section 13 of the MMDR Act, the Central Government notified Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 vide gazette notification G.S.R. 717 (E) dated 01.10.2021 further to amend Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter, 'MCR Rules').

3. Now, the undersigned is directed to refer to Rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960 (copy attached) and to say that clauses pertaining to sale of coal in the Coal Mine Development and Production Agreements (hereinafter, 'CMDPA') and Allotment Agreements executed with the lessees where coal is used for captive purpose are to be amended.

4. Accordingly, relevant standard amendment text may be noted as detailed in: -

Annexure-A:- in reference to CMDPAs (executed in Tranche 1, 2 and 3 of Auction) and Allotment Agreements (executed in Tranche 1 of Allotment) for captive usage of coal, and

Annexure-B:- in reference to CMDPAs (executed in Tranche 8 and 10 of Auction) and Allotment Agreements (executed in Tranche 6 of Allotment) allowing sale of coal up to 25 percent by captive lessees.

Annexure-C:- in reference to Allotment Agreements executed for allotment of Tubed, Talabira II & III, Amelia and Utkal D&E coal mines.

Thus, it is hereby notified that all existing CMDPAs and Allotment Agreements executed in the aforementioned tranches, with the lessees where coal is used for captive purposes stand amended in accordance with the annexed standard amendment texts.

(Manish Uniyal))
Under Secretary to the Government of India

To,

1. **All the Allocatees of coal mines allocated for captive end uses.**
2. **State Governments**
3. **Coal Controller's Organization**
4. Website of Ministry of Coal

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230139
CG-DL-E-04102021-230139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943
No. 575] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

‘(viiक) “खान का परिचालन” से पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से विस्फोटन, उत्खनन, कर्तन या खुरचन के पश्चात् प्राप्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या असम्मिलित सामग्री अभिप्रेत है ; ’

3. मूल नियमों में नियम 24ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“24ग. सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान किए गए खनन पट्टे की अवधि.—

(1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् कोयले या लिग्नाइट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे ।

(2) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व कोयले या लिग्नाइट के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम में निहित या उसे प्रदत्त सभी विद्यमान खनन पट्टे 50 वर्ष के लिए या 31 मार्च, 2030 तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रदत्त किए गए समझे जाएंगे ।

(3) राज्य सरकार, इस संबंध में खनन पट्टे के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए आवेदन पर खनिज पट्टे को एक समय में बीस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाएगी:

परंतु राज्य सरकार विहित समय सीमा के पश्चात् विस्तार के लिए आवेदन में देरी को माफ कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टे के अवधि का विस्तार नहीं प्रदान किया जाएगा जो निविदा के माध्यम से चयनित की गई है ।

(4) यदि राज्य सरकार द्वारा उपनियम (3) में उल्लिखित समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए किया गया कोई आवेदन पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व निपटाया नहीं जाता है, तो उस पट्टे की अवधि उस पर राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किए जाने तक विस्तृत हुई समझी जाएगी ।

(5) सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021(2021 का 16) के आरंभ की तारीख पर लंबित थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन समझे जाएंगे और उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे ।" ।

4. मूल नियमों के नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:--

"27क. आबद्ध खान के पट्टाधारी द्वारा कोयले या लिग्नाइट के विक्रय की रीति.—(1) कोई पट्टाधारी जहां आबद्ध प्रयोजन के लिए कोयले या लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है, खान से संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित कोयले या लिग्नाइट की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन यथा अनुज्ञात कुल मात्रा के ऐसे प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट विक्रय कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए खान के संबंद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षा उस वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में उक्त संयंत्र द्वारा उपभोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा होगी ।

स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजन के लिए उत्पादित, वितरित, एंड-यूज संयंत्र से संबद्ध उपयोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा और वितरित मात्रा पर अतिरिक्त रकम के संदाय का निर्धारण खान के परिचालन आधार पर किया जाएगा

स्पष्टीकरण 3.—अपशिष्ट, अग्राह्य या मिडलिंग का विक्रय इस नियम द्वारा निर्बंधित नहीं होगा ।

(2) धारा 8 की उपधारा (5) के अनुसार विक्रीत कोयले या लिग्नाइट की मात्रा के लिए पट्टाधारी, राज्य सरकार को स्वामिस्व का संदाय करते समय अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा, जो जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को स्वामिस्व या संदाय अन्य कानूनी संदाय या निविदा दस्तावेज अथवा नीलामी प्रीमियम में विनिर्दिष्ट संदाय, जहां कहीं लागू हो, के अतिरिक्त होगा ।

(3) पट्टाधारी पूर्व वित्तीय वर्ष में किए गए विक्रय के लिए किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रण संगठन और राज्य सरकार को प्ररूप **द** में स्वघोषणा प्रस्तुत करेगा ।

(4) किसी कंपनी या निगम को आबंटित कोयले की खानों से कोयले का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा, जिन्हें टैरिफ के लिए प्रतियोगिता बोली के आधार पर शक्ति परियोजना (जिसके अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी है) प्रदान किए गए हैं ।"

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट के विक्रय के लिए उपबंध केन्द्रीय सरकार के साथ पट्टाधारी द्वारा किए गए संबंधित करार में विहित पात्रता शर्तों और कार्य कुशलता प्राचलों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

5. मूल नियमों के नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"28. पट्टों का व्यपगमन.—(1) जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ नहीं हुआ हो या उत्पादन या प्रेषण प्रारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की सतत अवधि के लिए समाप्त हो गया हो, खनन पट्टा यथा स्थिति पट्टे के निष्पादन की तारीख से या उत्पादन और प्रेषण की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा ।

(2) खनन पट्टे का व्यपगमन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा और पट्टाधारी को भी संसूचित किया जाएगा ।

(3) जहां पट्टाधारी खनन अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमर्थ है या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पादन और प्रेषण समाप्त हो जाता है, वह राज्य सरकार को उक्त दो वर्ष की अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पहले उसका कारण दर्शित करते हुए ऐसी दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां पट्टाधारी उपरोक्त नियत समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है वहां दो वर्ष की समाप्ति पर पट्टा व्यपगत हो जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) वह कारण, जिनसे पट्टाधारी के लिए खनन संक्रियाएं करने या उत्पादन और प्रेषण को जारी रखना असंभव हो गया;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण पट्टाधारी के नियंत्रण के बाहर हैं;

(ग) वह कदम जो पट्टाधारी द्वारा ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए हैं; और

(घ) चाहे गए विस्तार की अवधि ।

(5) उपनियम (3) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ दो सौ रुपए की फीस संलग्न होगी ।

(6) राज्य सरकार, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्, उपधारा (3) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से, जिसको खनिज पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो, से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा अनुरोध को स्वीकार करते हुए या खारिज करते हुए कोई आदेश पारित करेगी:

परंतु ऐसा खनिज पट्टा उत्पादन और प्रेषण करने में विफल होने पर या एक वर्ष के लिए बढ़ाई गए अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण जारी रखने में असक्षमता पर व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा विस्तार पूरी पट्टा अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं प्रदान की जाएगी ।

(7) राज्य सरकार ऐसा आदेश अभिलिखित करने या जारी करने के पंद्रह दिन के भीतर उपनियम (2) के अधीन अभिलिखित या उपनियम (6) के अधीन जारी आदेश कोयला नियंत्रण संगठन, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और कोयला मंत्रालय को संसूचित करेगी । "।

6. मूल नियमों के नियम 28क का लोप किया जाएगा ।

7. मूल नियमों के नियम 64ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"64ख प्रसंस्करण के अधीन रहते हुए खनिजों के मामले में रायल्टी के संदाय भुगतान करना और भारित करना- पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्करण को विचार में लाए बिना अप्रसाधित अयस्क खनिजकोयला या लिग्नाइट पर रायल्टी , भारित की जाएगी:

परंतु रायल्टी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर से प्रेषण या उपभोग के समय देय होगी ।"

8. मूल नियमों में, नियम 64ग का लोप किया जाएगा ।

9. मूल नियमों में, अनुसूची I में, प्ररुप थ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप द

[नियम 27क, उपनियम (3) देखें]

स्वतः घोषणा

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 20..... से 31 मार्च, 20.....तक

वार्षिक विवरणी

सेवा में,

(i) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
कोयला मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ii) कोयला नियंत्रक
कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय
1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट,
लाल दिगही, बी बी डी बाघ
कोलकाता, पश्चिमी बंगाल-700001.

(iii) राज्य सरकार

(कोयला लिग्नाइट का उत्पादन, प्रेषण और स्टाक)

(टन में परिमाण की इकाई)

1. खान के ब्यौरे :

(क)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टेदार-स्वामी की रजिस्ट्रीकरण संख्या दें)	
(ख)	खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग)	खनिज का नाम (कोयला या लिग्नाइट) :	
(घ)	खान का नाम	

2. खान की अवस्थिति :

गांव	
पोस्ट-आफिस	
तहसील-तालुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स नं.	ई-मेल
फोन नं.	मोबाइल

3. पट्टेदार-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई-मेल के साथ) :

(क)	पट्टेदारस्वामी का नाम-	
(ख)	पता	
(ग)	जिला	
(घ)	राज्य	
(ड.)	पिन कोड	
(च)	फैक्स नं.	ई-मेल
(छ)	फोन नं.	मोबाइल
(ज)	पट्टेदार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	
(झ)	भार-साधक निदेशक	
(ण)	अभिकर्ता	
(ट)	प्रबंधक	

4. श्रेणीवार वार्षिक उत्पादन, ई यू पी अपेक्षा, ई यू पी उपयोग, विक्रय आदि ।

लिग्नाइट श्रेणी का कोयला	**गर्तमुख पर स्टाक खोलना (अग्रनीत किया गया)**	**उत्पादन**	**ई यू पी अपेक्षा**	**ई यू पी उपयोग**	**विक्रीत मात्रा**	**गर्तमुख पर स्टाक बंद करना**
कुल योग:						

5. घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए प्रभावित विक्रय-प्रेषण :

लिग्नाईट/ कोयले की श्रेणी	प्रेषण की प्रकृति (उपदर्शित करें कि क्या घरेलू विक्रय या घरेलू अंतरण या आबद्ध उपभोग या निर्यात हुआ है)	घरेलू प्रयोजनों के लिए				निर्यात के लिए		
		खरीददार/ पारेषिती का रजिस्ट्रीकरण संख्या जी एस टी एन ##	पारेषिती का नाम ##	मात्रा	विक्रय मूल्य (0रु)	देश	मात्रा	एफ ओबी . मूल्य (0रू)
कुल योग:								

यदि एक से अधिक खरीददार हैं तो अलग से उपदर्शित करें :

टिप्पण : खान स्वामी को घरेलू विक्रय मूल्य का सबूत देना आवश्यक है – बीजक की प्रतिलिपि के साथ ऊपर उत्कथित प्रत्येक श्रेणी के कोयले या लिग्नाइट की श्रेणी के लिए एफ ओ बी मूल्य (विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा; जहां आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाएगा)।

6. उत्पादन-शून्य उत्पादन में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ।

क) .....

ख).....

7. पूर्व खान मूल्य वार श्रेणी में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ।

क) .....

ख).....

स्थान ..... **हस्ताक्षर .....**

तारीख ..... **पूरा नाम .....**

पदनाम: स्वामी /अभिकर्ता /खान इंजीनियर/प्रबंधक।"

[फा. सं. 12012/2/2021-पी एस 1]

बी.पी. पति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 23 नवंबर, 1960 की संख्या जी.एस.आर. 1398 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए थे और दिनांक 29 मई, 2020 की संख्या जी.एस.आर. 331(अ) के जरिए अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के माध्यम से अंतःस्थापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 की उपधारा (4) को तदनुसार विद्यमान खान के पट्टों की अवधि को विहित करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के मामलों में खान के पट्टों की अवधि को विस्तार करने के लिए सशक्त करती है, विद्यमान पट्टों की अवधि को नियम 24ग की उपधारा (2) में विहित किया गया है और खान के पट्टों के नवीकरण के लिए लंबित आवेदनों को नियम 24ग के उपनियम (5) में खान के पट्टों की अवधि के विस्तार के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा । यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के माध्यम से भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

G.S.R. 717(E).—In exercise of powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules they shall come into force on the date of their publication in Gazette of India.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, (hereinafter referred to as the principal rules),in rule 2, in sub-rule (1), after clause (vii),the following clause shall be inserted, namely:-

'(viia) "run-of-mine" means the raw, unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting, digging, cutting or scraping from the mineralised zone of a lease area;'.

3. In the principal rules, after rule 24B the following rule shall be inserted, namely:-

"24C. Period of mining lease granted to Government companies or corporations.—

(1) All mining leases granted on or after the commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 to a Government company or corporation for coal or lignite shall be for a period of fifty years.

(2) All subsisting mining leases vested or granted to a Government company or corporation before commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 for coal or lignite shall be deemed to have been granted for fifty years or till 31st March 2030, whichever is later.

(3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for a further period of twenty years at a time:

Provided that the State Government may condone the delay in application for extension made after the prescribed time limit:

Provided further that no extension of period of mining lease shall be granted to a Government company or corporation that has been selected through auction.

(4) If an application for extension of mining lease made within the time mentioned in sub-rule (3) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended till the State Government passes an order on the same.

(5) All applications made by a Government company or corporation for renewal of mining lease which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (3).".

4. In the principal rules, after rule 27, the following rule shall be inserted, namely:-

"27A. Manner of sale of coal or lignite by the lessee of a captive mine.— (1)Any lessee may, where coal or lignite is used for captive purpose, sell coal or lignite up to such per cent. of the total coal or lignite produced in a financial year, as allowed under sub-section (5) of section 8, after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine.

Explanation 1.- For the purpose of this rule it is clarified that the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of coal or lignite consumed in the said plant in that financial year or a part thereof.

Explanation 2.- For the purpose of this rule, quantity of coal or lignite produced, sold, utilised in linked end-use plant and the payment of additional amount on the quantity sold shall be assessed on run-of-mine basis.

Explanation 3.-Sale of any tailings, rejects or middlings shall not be restricted by this rule.

(2) For the quantity of coal or lignite sold in accordance with sub-section (5) of section 8, the lessee shall pay to the State Government, at the time of payment of royalty, an additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act, which shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust or any other statutory payment or payment specified in the tender document or the auction premium, wherever applicable.

(3) Within one month of the end of a financial year, for sale made in the previous financial year, the lessee shall submit to the Nominated Authority, Ministry of Coal, Coal Controller's Organisation and to the State Government, a self-declaration in Form R.

(4) Sale of coal shall not be allowed from the coal mines allotted to a company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Projects)."

Explanation.-For the purpose of this rule, it is clarified that the provision for sale of coal or lignite as prescribed in this rule shall not affect the eligibility conditions and efficiency parameters prescribed in the respective agreements entered into by the lessee with the Central Government.

5. In the principal rules, for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:-

"28. Lapsing of Leases.— (1) Where production and dispatch has not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of production or dispatch, the mining lease shall lapse on the expiry of the period of two years from the date of execution of the lease or as the case may be, discontinuance of the production and dispatch.

(2) The lapsing of the mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.

(3) Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, requesting for an extension of such period of two years by a further period not exceeding one year, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.

(4) Application made under sub-rule (3) shall specify—

(a) the reasons on account of which it will not be possible for the lessee to undertake mining operations or continue production and dispatch;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee;

(c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons; and

(d) the period of extension sought.

(5) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of two hundred rupees.

(6) The State Government shall, after examining the application, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period of one year:

Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.

(7) The State Government shall communicate to the Coal Controller's Organisation, Nominated Authority and Ministry of Coal the order recorded under sub-rule (2) or issued under sub-rule (6)within fifteen days of recording or issuing of such order.".

6. In the principal rules, rule 28A shall be omitted.

7. In the principal rules, for rule 64B, the following rule shall be substituted, namely:-

"64B. Charging and instance of payment of royalty in case of minerals subjected to processing.— The royalty shall be charged on run-of-mine coal or lignite irrespective of its processing within or outside the leased area:

Provided that the royalty shall be payable at the time of dispatch from or consumption within the leased area.".

8. In the principal rules, rule 64C shall be omitted.

9. In the principal rules, in Schedule I, after Form Q, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form R

(*Rule 27A (3)*)

Self-declaration

For the financial year 1st April 20 _____ to 31st March 20 _____

ANNUAL RETURN

To

(i) The Nominated Authority
Ministry of Coal
Shastri Bhawan, New Delhi

(ii) The Coal Controller
Office of the Coal Controller's Organisation
1, Council House Street,
Lal Dighi, BBD Bagh
Kolkata, West Bengal-700001

(iii) State Government

(PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS OF COAL/LIGNITE)

(Unit of Quantity in Tonnes)

1. Details of Mine:

(a)	Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee-Owner)	
(b)	Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c)	Name of the Mineral (Coal OR Lignite):	
(d)	Name of Mine	

2. Location of the Mine:

Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No:	E-mail:
Phone No:	Mobile:

3. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):

(a)	Name of Lessee-Owner	
(b)	Address	
(c)	District	
(d)	State	
(e)	PIN Code	

(f)	Fax No.:	E-mail:
(g)	Phone No:	Mobile:
(h)	Registered Office of the Lessee	
(i)	Director in-charge	
(j)	Agent:	
(k)	Manager:	

4. Yearly **Grade-wise Production, EUP Requirement, EUP Utilisation, Sale etc.**

Lignite/ Grades of coal	**Opening stock at pit-head (Carried Forward)**	**Production**	**EUP Requirement**	**EUP Utilisation**	**Quantity Sold**	**Closing stock at pit-head**
Grand Total:						

5. **Sales- Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports**:

Lignite/Grade of coal	Nature of Dispatch *(Indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number/ GSTN of the buyer/ consignee ##	Consignee name##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value (₹)
Grand Total:								

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE: - Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of coal or lignite quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

6. **Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the year compared to the previous year.**

a) .....

b) .....

7. **Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.**

a) .....

b) .....

Place:…… Signature……..……...

Date……. Name in Full……..……..

Designation: Owner/Agent/Mining Engineer/Manager".

[F. No. 12012/2/2021-PS1]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1398, dated the 23thNovember, 1960 and lastly amended vide number G.S.R 331(E) dated the 29th May, 2020.

Explanatory Memorandum

Sub-section (4) of Section 8 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957inserted through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) empowers the Central Government to prescribe the period of existing mining leases and to extend the period of mining leases in case of Government companies or corporations. Accordingly, the period of existing mining leases has been prescribed in sub-rule (2) of rule 24C and the pending applications for renewal of mining leases shall be deemed to be applications for extension of period of mining lease in sub-rule (5) of rule 24C. It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect through these rules.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.04 21:48:04 +05'30'

Annexure-A

For existing CMDPAs executed in Tranche 1&2 and Tranche 3 of Auction for captive usage of coal and for existing Allotment Agreements executed in Tranche 1 of Allotment for captive usage of coal

Clause 8.1 of the existing agreement shall be substituted by the following clause:-

8.1. **Utilisation of Coal in the Specified End Use Plant**

8.1.1. Except as otherwise provided in this Clause 8, the coal extracted from the Coal Mine shall be utilised by the Successful Bidder [*or Allottee*] strictly in the Specified End Use Plant; and shall not be utilised for any other purpose whatsoever, either directly or indirectly.

8.1.2. Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Successful Bidder [*or Allottee*], after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine, may sell coal up to fifty percent of the total coal produced in a financial year. Manner of sale shall be as prescribed in Rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960. For the actual quantity of coal sold in open market the successful bidder [*or Allottee*] shall pay to the State Government, an additional amount as per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Quantity of coal produced/sold/utilized in the linked end use plant shall be assessed on run-of-mine (ROM) basis.

8.1.3. Successful bidder [*or Allottee*] shall submit a self-declaration in Form R as per rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960.

*****

Annexure-B

For existing CMDPAs executed in Tranche 8 and 10 of Auction and existing Allotment Agreements executed in Tranche 6 of Allotment

1. **Clause 8.1 of the existing agreement shall be substituted by the following clause:**

8.1. **Utilisation of Coal in the Specified End Use Plant**

8.1.1. Except as otherwise provided in this Clause 8, the coal extracted from the Coal Mine shall be utilised by the Successful Bidder [*or Allottee*] strictly in the Specified End Use Plant; and shall not be utilised for any other purpose whatsoever, either directly or indirectly.

8.1.2. Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Successful Bidder [*or Allottee*], after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine, may sell coal up to fifty percent of the total coal produced in a financial year. Manner of sale shall be as prescribed in Rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960. For sale of coal up to twenty-five per cent of annual production, the successful bidder [*or Allottee*] shall be required to pay an additional premium [*or Additional Reserve Price*] of 15% of its final bid price [*or Reserve Price*] on per tonne basis, for the actual quantity of coal sold in open market. For sale of coal more than twenty-five per cent and up to fifty per cent of annual production the additional premium [*or Additional Reserve Price*] shall be paid as per Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the actual quantity of coal sold in open market. The additional premium [*or Additional Reserve Price*] will be over and above the final bid price [*or Reserve Price*]. Quantity of coal produced/sold/utilized in the linked end use plant shall be assessed on run-of-mine (ROM) basis.

8.1.3. The Successful bidder [*or Allottee*] shall submit a self-declaration in Form R as per rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960.

2. **Clause 8.5.1 of the existing agreement shall be substituted by the following clause:**

8.5.1. Any coal extracted from the Coal Mine which is in excess of the requirements/ utilisation in accordance with the provisions of Clauses 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4, i.e., if due to maintenance or shutdown or such other unavoidable reasons, beyond the control of Successful Bidder [*or Allottee*], during any part of the year, the Successful Bidder [*or Allottee*] is not able to use the coal produced to meet the requirement of the specified end use plant or own consumption, such excess coal shall be required to be supplied to CIL at the terms and conditions specified at Clause 8.5.3.

Provided however, such sale should not exceed 50% of the annual production of coking coal **[**and non-coking coal respectively] from the Coal Mine.

3. Illustrations pertaining to utilization of coal placed below Clause 8.5 of the existing agreement shall be substituted by the below illustrations:

Step	**Clause**	**Example**
1	As per clause 8.1, the Successful Bidder [*or Allottee*] shall after meeting the requirement of specified end use plant(s) is allowed to sell upto 50% of the actual production (ROM) in open market.	If in a financial year, 100 MT coal is actually produced (ROM) – 40 MT is utilised for meeting the requirement in SEUP(s) then 50 MT can be sold in market
2.	As per clause 8.2, Middlings & Rejects which cannot be utilised in the SEUP(s) of the Successful Bidder [*or Allottee*], may be sold with prior approval of CCO	So, out of 40 MT [i.e. required to be utilised in SEUP(s)], if 30% Middlings and Rejects are obtained on washing which cannot be utilised in SEUP(s), then such 30% of 40 MT (= 12 MT) can be sold and remaining 70% of 40 MT (= 28 MT) is to be utilised in SEUPs
3.	As per clause 8.3 and 8.4, the Successful Bidder [*or Allottee*] can make arrangement for optimum utilisation and utilise coal in other end use, respectively.	So, Successful Bidder [*or Allottee*] can utilise coal as per clause 8.3 and 8.4 out of 100 MT (ROM) or 40 MT (which is required to be utilised in SEUP) or 70% of 40 MT (after washing), as the case may be
4.	(a) As per clause 8.5, any coal extracted which is in excess of requirement / utilisation of coal in accordance with provision of 8.1, 8.2, 8.3 & 8.4 is to be required to be sold to CIL. (b) Provided that sale should not exceed 50% of annual production.	So, out of 70% of 40 MT = 28 MT (which is to be utilised in SEUP(s) to meet its requirement as per step 2), any quantity which cannot be utilised is to be sold to CIL. This sale is subject to 50% limit as mentioned in proviso of clause 8.5

Note: *The above mentioned illustrations are merely for reference purpose and in case of inconsistency, the provision of Clause 8 shall prevail.*

*****

Annexure-C

For existing Allotment Agreements executed for allotment of Tubed, Talabira II & II, Amelia and Utkal D & E coal mines.

After Clause 8.1.2 of the existing agreements the following clauses shall be inserted:-

"

8.1.3 Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Allottee, after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine, may sell coal up to fifty percent of the total coal produced in a financial year. Manner of sale shall be as prescribed in Rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960. For the actual quantity of coal sold in open market the allottee shall pay to the State Government, an additional amount as per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Quantity of coal produced/sold/utilized in the linked end use plant shall be assessed on run-of-mine (ROM) basis.

8.1.4 The allottee shall submit a self-declaration in Form R as per rule 27A of the Mineral Concession Rules, 1960."

*****